



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 844)

Name of Candidate	ANITA YADAV		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	16663
Center	MN, DELHI	Date	29/10/16

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)। 2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH. इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। 3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए। 7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।
1	12.5		
2	12.5		
3	12.5		
4	12.5		
5	12.5		
6	12.5		
7	12.5		
8	12.5		
9	12.5		
10	12.5		
11	12.5		
12	12.5		
13	12.5		
14	12.5		
15	12.5		
16	12.5		
17	12.5		
18	12.5		
19	12.5		
20	12.5		
Total Marks Obtained:			
Remarks:			

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. It has been assessed that radicalisation is a security threat to India. Explain the basis of such an assessment with examples. What are the key pillars of the counter radicalisation strategy of the government?

प्रायः यह आकलित किया जाता है कि कट्टरता (रेडिकलाइजेशन) भारत के लिए एक सुरक्षा संबंधी खतरा है। इस तरह के आकलन के मूलाधारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कट्टरता से निपटने के लिए सरकार की रणनीति के प्रमुख आधार स्तंभ क्या हैं?

धार्मिक, भाषापी, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय कट्टरता भारत की सुरक्षा के समझ की चुनौती है। इससे समाज में संघर्ष व तनाव उत्पन्न होते हैं। कट्टरता के कारण ही भारत में संप्रदायवाद, क्षेत्रीयवाद आधारित असमाजवादी भाँदोलन, भाषावाद, जातिवाद, आतंकवाद जैसी समस्याएँ उत्पन्न रही हैं।

1984 के सिख हत्या, 2002 गौधरा काण्ड, 2005 बिसाहिड़ा आतंकवाद, खातिस्तान की माँग, NSCN द्वारा नागासिम की माँग, उत्तर-दक्षिण विवाद, गराही मानुष, भसनी-विहरी विवाद कट्टरता के कारण घटित घटनाएँ ही हैं। वर्तमान साक्षर युग में इन समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है।

सोशल मीडिया, भूतसंस्कृत शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऐसे

विचारों को फैलाया जा रहा है। इससे भारत की एकाग्रता, अखण्डता के व संप्रभुता के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

इन समस्याओं से निवृत्ति के लिए सरकार की रणनीति का व्यापक व दूरदर्शी दृष्टिकोण पर आधारित होना आवश्यक है।

- सरकार द्वारा कटुतरा फैलाने वाले व्यापारियों व संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
- युधिष्ठा तंत्र को मजबूत बनाना ताकि ऐसी घटना होने से पूर्णतः उसे रोका जा सके।
- सोशल मीडिया पर 'भॉटो फिल्टर' लागू करना।
- अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों में सहिष्णुता, संतुलित दृष्टिकोण जैसे विषयों का अध्ययन शामिल करना।
- प्रेषकतावादी भावों से निवृत्ति के लिए परमार्थ सुरक्षा बल
- सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक

भाषाएँ बहुत दौंचै का पर्याप्त विकास किया
जाना चाहिए।

- शिक्षा, रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था
ताकि युवा वर्ग कटहला की तरफ
आकर्षित न हो।

इस प्रकार उत्तम स्तर पर प्रशिक्षण
के द्वारा कटहला को रोका जा
सकता है।

2. Arguments on Siachen issue often move around the idea of demilitarisation. Examining the key attributes of the Siachen issue explain the basis of arguments regarding its demilitarisation? Also highlight the arguments against such an idea.

सियाचिन मुद्दे पर प्रस्तुत तर्क अक्सर विसैन्यीकरण के विचार के आस-पास मंडराता रहता है। सियाचिन मुद्दे से जुड़े प्रमुख पहलुओं का परीक्षण करते हुए इसके विसैन्यीकरण संबंधी तर्कों के मूलाधारों की व्याख्या कीजिए? साथ ही इस तरह के विचार के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों पर भी प्रकाश डालिए।

सियाचिन हिमालय का एक ग्लेशियर है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है। सियाचिन की सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण होने के कारण दोनों ही देश इस पर दावा प्रस्तुत करते हैं। परंतु इस क्षेत्र के विसैन्यीकरण की मांग समय-समय पर उठती रहती है।

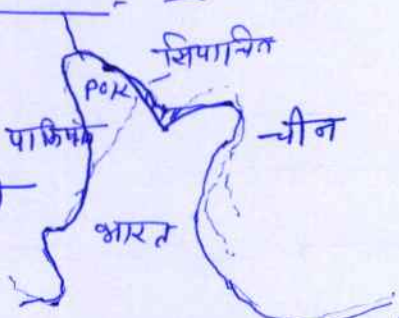
विसैन्यीकरण के पक्ष में तर्क -

- सियाचिन की सुरक्षा के लिए सैन्य खर्च बहुत अधिक है। प्रतिदिन करोड़ों रुपये इस पर खर्च किए जाते हैं।
- भूतपिंड कम तापमान होने के कारण सैनिकों की समस्या।
- भूतपिंड से भी कम तापमान के कारण हाइपोथर्मिया व फ्रॉस्ट बाइट की समस्या।
- सैनिकों में भ्रम गलत, आसिद्धि, भ्रम, भ्रमंगत जैसी समस्याएँ।
- हिमखलन से पिछले 10 वर्षों में लगभग 824 सैनिक दब चुके हैं।

इससे सेना की नुकसान हो रहा है।

- भारत व पाकिस्तान के मध्य तनाव बढ़ रहा है।

विसैत्तीकरण के विपदा है।

- सियाचीन की सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इस पर पाकिस्तान नियंत्रण से भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षित रहती है। 
- यदि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया तो भारत के खिलाफ इसका उपयोग किया जा सकता है।
- पाकिस्तान - चीन गठबंधन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। दोनों मिलकर इस सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
- पूर्व में विसैत्तीकरण के परिणाम सुखद नहीं थे। जैसे बरगील युद्ध।
- दोनों देशों ने विसैत्तीकरण पर सहमति नहीं है। सीमा विवादों पर भी विवाद। भारत ऊपर पश्चिमी सीमा को तथा पाकिस्तान और पूर्वी सीमा को प्राप्ता देगा है।
- सियाचीन की विसैत्तीकरण करने

के लिए दोनो देशों के मध्य सहमति होना
आवश्यक है। इसके लिए सीमांकन भी होना
आवश्यक है। वर्तमान के भारत की सीमा
NS 9842 तक है।

3. Money laundering and terrorism have strong inter linkages. Illustrate. In this context, how far do the steps taken by the government confirm with the international commitments?

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद मजबूती से एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा उठाए गए कदम किस हद तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हैं ?

आतंकवादी समूहों के लिए वित्त रकत या
रूचन के समान है। वर्तमान में आतंकवाद
के विनीय साधन धुलाने के लिए मनी
लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियों को बैंक
बनाने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से प्राप्त
धन को आतंकवादी गतिविधियों में लागू
किया जाता है। हवाला, पैसों का कर, स्मॉलिंग,
स्मॉलिंग, बैंक फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड भ्रष्टाचार
जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया जाता है।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में तकनीकी
का प्रसार होने के कारण आतंकवादी धन
की प्राप्ति तकनीकी माध्यमों से हो रही है।

आतंकवाद व मनी लॉन्ड्रिंग दोनों
ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्याएँ हैं।
भारत भारत ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर
पर इसके लिए प्रयास किए हैं। अन्तः

- स्तर पर इसके लिए कारनेसिल एक्सन
रास्क फॉर्स का गठन किया गया है जिसका
उद्देश्य आतंकवाद के विरोध सीमाओं को
सीमित करना है । भारत इसका सदस्य है ।
सभी राज्यों ने टेरर फंडिंग पर रोक
लगाई है ।
- बैसल तॉर्म्स का चालन कारतबरीतरह से
कर रहा है ।
 - एपेक मनी लॉड्रिंग कानूनों को कारतबरी
भाधार बनाया है ।
 - भारत में प्रवर्तन निदेशालय (डी)
राँ, भाव भादि इसके लिए काम करने
वाली संस्थाएँ हैं ।
 - फाइनेंस इन्फोर्मेशन इमार् (FIIU-IND)
की स्थापना भारत के द्वारा की गई है ।
 - मनी लॉड्रिंग के लिए 2002 में कानून
बनाया गया है जिसे 2008 में संशोधित
किया गया ।
 - इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ
डबल टैन्डीसन अवीड्डेन्स करार किये ।
इस प्रकार भारत ने अपने

मनी लॉन्ड्रिंग मानक अन्तराष्ट्रीय मानकों
के समान रखे हें।

4. Longstanding issue of insurgency in the Northeast highlights the linkage between violence, remoteness, underdevelopment and alienation. Elaborate. Also, suggest some corrective measures for a lasting resolution of the conflicts in this region.

पूर्वोत्तर में लम्बे समय से विद्यमान उग्रवाद का मुद्दा वस्तुतः हिंसा, दूरी, अल्पविकास, और अलगाव की भावना के मध्य के संबंधों पर प्रकाश डालता है। सविस्तार व्याख्या कीजिये। इसके साथ ही इस क्षेत्र में संघर्ष के एक स्थायी समाधान के लिए कुछ सुधारात्मक उपायों का सुझाव भी दीजिए।

भारत के पूर्वोत्तर में बोडो, NSCN, गारो
लिवरेशन फ्रंट, मणिपुर लिबरेशन आर्मी जैसे
कई भ्रूणवादी संगठन भारत से अलग
होने की मांग कर रहे हैं। इसके कई
कारण हैं: —

ऐतिहासिक — पूर्वोत्तर के ज्यादातर क्षेत्र जंगली
रहे हैं। इनके दस्तलेप से इन क्षेत्रों में निवास
की समस्या से उत्पन्न भ्रंशपूर्ण इसका कारण है।

नस्लीय — पूर्वोत्तर के क्षेत्र मंगोलोइड नस्ल
के होने के कारण भारत से घुसकर आ रहे हैं।

नस्लीय के साथ भाषाई व धार्मिक
रूप से भी इनके घुसकर आ रहे हैं।

राजनीतिक — राजनीतिक रूप से ये क्षेत्र भ्रूण-
भ्रंश रहे हैं। क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय उद्देश्य
भारत से फिनाई हैं।

भौगोलिक — भौगोलिक रूप से क्षेत्र बीच
भारत के 22 किलोमीटर के चिकन के
गलिपारे से ही जुड़ा हुआ है। मल

कनेक्टिविटी की समस्या है।

भार्षिक — भार्षिक रूप से यह क्षेत्र पिछड़ा है
जटिल कर्मागतिक संरचना के कारण भार्षिक
श्रुत फॉर्म का अभाव है।

गरीबी, बेरोजगारी की समस्या है। इस,
तस्करी आदि के कारण भुवा पीपी की क्षमता
का उपयोग नहीं हो पा रहा। उच्च शिक्षण
संरक्षण, अस्पताल आदि का अभाव है।

सांक्रांतिक व सौकरांतिक पिछड़ा है। शिक्षा की
उचित व्यवस्था नहीं है। वर्तमान तकनीकी युग में
इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्क का अभाव है।
इन सभी कारणों से पूर्वोक्त के
अलगवा की भावना विद्यमान है। इसके साथ ही
चीन द्वारा अलगवावादी गुटों का समर्थन भी
इसने शुरू कर दिया है।

स्थाई समाधान हेतु उपाय:-

तात्कालिक — तात्कालिक रूप से इस क्षेत्र के
का गुरु व्यवस्था का उच्चाती क्षमात्वपन भाव
रूप है, ताकि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास
आवृत हो।

- अलगवावादी गुटों का समाया।
- प्रथमतावादी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर
कठ की व्यवस्था।
- सुरक्षा बलों की पैनाती। (भार्षिक का)

दुरुपयोग पर रोक

दीर्घकालिक घाप — क्षेत्र में बिनास को बढ़ावा
दिया जाए।

- आधारभूत ढांचे का विकास / स्कूल, अस्पताल
आदि की स्थापना
- स्थायी लोंगों की घमासों के भारीहारी
- कृषि, पर्यटन को बढ़ावा
- सड़क, रेल, वायु आदि द्वारा कनेक्टिविटी
बढ़ाना।
- निश्वास बढ़ावा के उपाय। नेगटिव ड्रा
कॉर। पूर्वोत्तर के राजनैतिक स्थिति
- अन्धजातीय पंचशील का पालन
- लस्करी, ड्रग्स आदि को रोकना।

विषय 2020 जैसे कार्पेटों का उन्नी
प्रियान्वयन / नस्लीय अंदरूनी को रोकने के
लिए बेजबरोहों सहित की सुझावों
का उद्देश्य प्रियान्वयन।

5. While on the one hand China's One Road One Belt initiative poses security concerns and challenges for India, on the other, it can help improve India's connectivity to major markets and resource supplies. Discuss.

जहाँ एक ओर चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' पहल भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं और चुनौतियां खड़ा करता है, वहीं दूसरी ओर यह संसाधनों की आपूर्ति और प्रमुख बाजारों तक भारत की कनेक्टिविटी (संयोजकता) को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। चर्चा कीजिए।

'वन बेल्ट वन रोड नीति' चीन द्वारा प्रेरित
व अफ्रीका की एशिया से सड़क मार्ग से
जोड़ने की नीति है। यह सिल्क रूट का एक
हिस्सा है। भारत के लिए इस परियोजना
संबंधी कई चिंताएँ हैं -

- यह योजना चीन की है। किसी अंतराष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई नहीं है।
- इसका प्रयोग चीन स्वयं के हित के कर सकता है।
- इस योजना के तहत पाकिस्तान चीन आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो 2014 से होकर गुजरेंगा। इससे भारत की आपूर्ति है। भारत की सीमा सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है।
- चीन द्वारा कुछ देशों के साथ मिलकर कार्गो जहाजों के लिए चुनौती खड़ी की जा सकती है।

वहीं दूसरी ओर वर्तमान विश्व में भारत के लिए इस परियोजना से जुड़ने से अनेक लाभ हो सकते हैं -

- वर्तमान विश्व में आर्थिक संबंध राजनीति

संबंधों का निष्कारण कर रहे हैं। इस कारण विश्व से कटकर नहीं रह जा सकता।

- यूरोप व अमेरिका जैसे विकसित देशों में गंदी के कारण भारतीय माल की मांग कम हो रही है। इस निर्मित चार्ज से की प्रति पाश्चिमी एशिया व अफ्रीकी देशों से की जा सकती है। वन बेल्ट से जुड़कर भारत इन देशों तक पहुँच बना सकता है।

- पाश्चिमी एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया अफ्रीका में भारतीय माल की मांग है। इसकी प्रति चीन द्वारा की जा सकती है यदि भारत इस परिप्रेक्ष्य से अपने आप को बाहर रखता है।

- 21 वीं सदी एशिया की है अतः चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति से भारत को प्रयत्न करना और के लिए मुकसानदायक होगा।

- भारत इन देशों से विभिन्न कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। इससे भारत को लाभ होगा।

- भारतीय प्रवासियों के इतिहास से भी लाभदायक है।

मतः भारत की सुरक्षा से बिना कोई
समझौता किए भारत की इस योजना
से जुड़ना ~~ना~~ चाहिए। इसके अनेक
बाधा हैं। परंतु अपनी अपनी भाषाओं
का सम्बोधन किए जाने की आवश्यकता
है।

6. NATGRID was an ambitious step involving intelligence reforms, however, it remained a non-starter. Explain. In the context of recent initiatives to revive the NATGRID and the challenges it faced previously what steps are required to make it effective?

नेटग्रिड (NATGRID) इंटेलिजेंस सुधारों से सम्बंधित एक महत्वाकांक्षी कदम था, हालांकि यह शुरू नहीं हो पाया। व्याख्या कीजिए। नेटग्रिड को पुनर्जीवित करने की हाल की पहल और पूर्व में इसके द्वारा सामना की गयी चुनौतियों के संदर्भ में, इसे प्रभावी बनाने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

नेटग्रिड के माध्यम से ऑनलाइन सूचनाओं का भाषान-उपान सुरक्षा एकीकरण व विभिन्न विभागों के मध्य किया जाएगा। यह एक साझा प्लेटफॉर्म है जहाँ आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का संकलन किया जाएगा।

इसमें लगभग 11 प्रकारी सूचनार्थ संकलित की जाएंगी। इसके आतंकवाद से संबंधित व संबंधित लोगों का डेटा होगा। इस सूचना का उपयोग 1. संचालन व विभाग कर सकते हैं। जैसे भारी बी, ईटी, सीपीआर, राइफल्स राज्यों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कुछ राज्यों द्वारा भाषा व इह राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण इसे आसिय में नहीं लाया गया। परंतु वर्तमान में इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- राज्यों की स्वायत्तता के दृष्टिकोण की संभावना के डर से राज्यों द्वारा असहमति /
- उद्द राजनैतिक रुद्धावाप्ति का अभाव
- पर्याप्त आधारभूत ढांचे व तकनीक का अभाव
- विभिन्न एजेंसियों व संस्थाओं के समन्वय व भापसी सहमति का अभाव /
- तकनीकी क्षमता का उन्नयन नहीं होना /
- राज्य पुलिस को डारा बसा करने की अनुमति नहीं है। यह इसकी पुरख करी है।

प्रभावी बनाने के कदम

- तकनीक का पर्याप्त विकास व उपयोग
- भापसी समन्वय - केन्द्र व राज्यों के मध्य तथा विभिन्न संस्थाओं के मध्य
- डारा की सुरक्षा की ^{पुरका} ~~सुरक्षा~~ व्यवस्था क्योंकि हैकिंग से पूरे सुरक्षा मंत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है /
- राज्य - पुलिस को डारा में सचेदारी
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से भी सहयोग

• पिपाद के मुद्दी का समाधान

वर्तमान साबर मुग ने बंद
भारतवादी के खतरे की रोकने के
लिए नैरसिड इस पक्कानी उपकरण
साबित हो सकता है।

7. India's national security architecture faces a difficult task in detecting digital intrusion in cyberspace. What are the challenges India faces w.r.t. Digital Intrusion? How can these challenges be overcome?

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना, साइबर स्पेस में डिजिटल घुसपैठ का पता लगाने में मुश्किलों का सामना कर रही है। डिजिटल घुसपैठ के सन्दर्भ में भारत किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है?

स्पेस टर्मिनलों की जैसे उपग्रह आदि सैद्धांतिक सूचनाओं में तकनीकी रूप से घुसपैठ कर उनका स्वार्थपूर्ण उपयोग डिजिटल घुसपैठ कहलाता है। वर्तमान में संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह पर आधारित है। इसमें दैनिक जीवन की गतिविधियों से लेकर सुरक्षा तक की सभी क्रियाएँ शामिल हैं। यदि इस क्षेत्र में घुसपैठ कर ली जाएगी भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

सुरक्षित संचार उपग्रह व इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं को यदि हक कर लिया जाए तो भारत की सुरक्षा जागरूकता के धारों लग सकती है। भारत के इसरी द्वारा छोड़े गए उपग्रह के कड़ेकाउ के सबूत मिलेंगे।

यदि कड़ेकाउ इतने सूक्ष्म स्तर पर की जाती है कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसके लिए कई उपायों का

उपलब्ध नहीं हैं। न ही भूतरीष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए मानक तैयार किए गए हैं।

उपभूट लॉच करने के छोटे बजटों से कपने का यह एक आसान उपाय है। इस कारण अन्य देशों की सरकारों द्वारा इसका विरोध भी नहीं किया जाता।

भारत पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसी देशों से घिरा होने के कारण ज्यादा निरंतर है।

उपाय:-

- तकतीनी सुरक्षा बढ़ाकर
- भूतरीष्ट्रीय स्तर पर काबू बनाने के प्रयास
- साइबर सुरक्षा की सुनिश्चित परिकल्पना देकर।
- इसे गैरमानवनी चोखित कर कमीरेक की व्यवस्था की जा सकती है।

8. Relations with Iran hold a lot of potential for India's ambitions for West Asia and beyond, however, realising this potential also involves certain global and regional challenges. Examine.

ईरान के साथ संबंध वस्तुतः पश्चिम एशिया और उससे परे भारत की महत्वाकांक्षा के लिए संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, तथापि इस संभावना को साकार करने के मार्ग में कुछ वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियां भी हैं। परीक्षण कीजिए।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की देखते हुए भारत व ईरान के मध्य संबंध भारत के लिए लाभदायक हैं।

भारत द्वारा शुरू की गई "लुक वैस्ट" नीति के माध्यम से पश्चिम एशिया के देशों के साथ बणिज् संबंध स्थापित करने के लिए ईरान एक माध्यम हो सकता है। ईरान के बावहार बंदरगाह को इसके लिए प्रमुख माना जा रहा है। चूंकि अरब सागर के माध्यम से भारत का ज्यादातर आयात- निर्यात होता है। यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व सेण्ट्रल एशिया के लिए ईरान एक कनेक्टिंग लिंक है।

भारत अपनी पहुँच सेंट्रल एशिया विशेषकर अफगानिस्तान तक ईरान के द्वारा बना सकता है। इसी कारण अफगानिस्तान की जरूरत- दैनिक शीट को बावहार से जोड़ा जा रहा है इस

चीन को मार्शल द्वीप 'नाम दिया' गया है। इसके द्वारा तातिवान का इस क्षेत्र में प्रभाव कम करने में मदद मिल सकती है। चीन व पाकिस्तान के गठबंधन को इसके माध्यम से कमतर किया जा सकता है। भारत की रुनी आवश्यकता की दृष्टि से इसका इलाका भी जा रही है। इस कारण ईरान के साथ भारत के संबंधों के बीच निहितार्थ है।

~~संभव~~ परंतु इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं: -

वैश्विक —

- ईरान के पास ~~अ~~ परमाणु हथियार बनाने संबंधी सबूतों के चलते व्यापक मार्ग पर निबंध लागू किए गए हैं। इस कारण अमेरिका, इजरायल जैसे देश ईरान के खिलाफ हैं।
- वर्तमान में अमेरिका व रूस के माध्यम विद्यमान तनाव के कुछ बिंदुओं में से एक ईरान भी है।
- ईरान विश्व समुदाय में अलग-थलग सा है।

क्षेत्रीय: —

- ईरान शिया राष्ट्र है, इस कारण पाश्चिमी एशिया के सुन्नी बहुल क्षेत्र में वह सक्रिय अरब के जैसे देशों के विरोधी गुट में माना जाता है, जबकि भारत के इन देशों से भी अच्छे संबंध हैं।
- वर्तमान में सीरिया की समस्या में भी ईरान का क्षेत्रीय ताकतों के साथ लगाव पूर्ण संबंध है।
- इमरान के साथ कटुतापूर्ण संबंध जबकि भारत इमरान के संबंध अच्छे रहे हैं।
- चीन की इस क्षेत्र में बढ़ती ताकत 2002 के आख्यान से।
- पाश्चिमी एशिया व अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में मशरूम।

परंतु फिर भी भारत ईरान संबंध उभारि पर है जो कि दोनों देशों के लिए उपयोगी है।

9. The internal crisis in Nepal over the past few years has given concrete shape to the fears of China gaining upper hand vis-a-vis a traditionally influential India. Elaborate. What can India do to further strengthen its ties with the Himalayan nation?

पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के आंतरिक संकट ने पारंपरिक रूप से प्रभाव रखने वाले भारत पर चीन द्वारा बढ़त लिए जाने के भय को ठोस आकार प्रदान किया है। विस्तारपूर्वक बताईए। इस हिमालयी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को अधिक मजबूत करने हेतु भारत और क्या कर सकता है?

नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना के कारण कुछ संक्रमणकालीन समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे भारत व नेपाल के मध्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि नेपाल के संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नेपाली मूल व मधेशी लोगों के मध्य भेदभाव करती हैं। मधेशी तयारी में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इस कारण भारत इन प्रायश्चित्तों का क्रियेष्ट करता है।

भारत व नेपाल के मध्य उत्पन्न तनाव के कारण ही भारत से नेपाल की ओर आने वाले ईंधन व भन्न के निर्यात को नेपाल द्वारा रोक रखा नहीं जा रहा है। इस कारण वहाँ भन्न की समस्या उत्पन्न होने पर नेपाल ने भारत पर सख्त रोकने का आरोप लगाते हुए चीन से सहायता प्राप्त कर ली। साथ ही भारत व नेपाल के कुछ प्रधान मंत्रियों ने अपनी पुष्प भाषिकाओं

भाषाही चीन की गह। जहाँ परम्परागत रूप से वे चीन जाते थे।

चीन द्वारा नेपाल में टाइवे का निर्माण भी किया जा रहा है। कीलगाह के दरगाह के किल्ले के रूप में चीन अपने केदरगाह से नेपाल को जोड़ने की योजना बना रहा है।

चूँकि नेपाल भारत-चीन के मध्य बफर राष्ट्र है मत, इससे भारत की सुरक्षा को खतरा पहुँचने की संभावना है। नेपाल - भारत की कौड़ी मुली है। इससे भारत में भारतीय नाक, तस्करी, ड्रग्स, जाली मुद्रा का खतरा बढ़े। नेपाल के साथ भारत के सामंजस्य संबंधों की स्थापना के लिए विनम्र विषयों पर बातचीत की जा सकती है। —

• नेपाल की संस्कृति को बनाए रखते हुए मध्यासीय से संबंधित समस्या का समाधान करने में भूमिका खेपना करना।

• नेपाल की आवश्यक भाषिक व अन्य सहायता करना।

- लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक उचित उपाय करना,
 - 1949 की मैत्री संधि पर पुनर्विचार करना
 - नेपाल के से काफी संख्या में लोग भारत में काम करने आते हैं। उनकी सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखना।
 - नेपाल के नागरिक भारत की कुछ सरकारी नौकरियों में भी भौगीदार हो सकते हैं जैसे गौरखा रेजीमेंट
- भाषायी, धार्मिक, क्षेत्रीय, नस्लीय सत्तावादी का लाभ लेते हुए भारत की नेपाल के साथ संबंधों में बाधा डालने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए।
- भारत को नेपाल के सतत विकास के लिए निर्यात के रूप में रखने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए।

10. The Trans-Pacific Partnership agreement (TPP), touted as the world's biggest trade deal to date, has danger of bending the WTO rules. In this context, discuss the impact TPP can have on India's foreign trade. What are the options that India has to deal with the issues arising out of the TPP?

विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते के रूप में प्रचारित ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टी.पी.पी.) समझौते द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के नियमों को प्रभावित करने की आशंका है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के विदेश व्यापार पर टी.पी.पी. के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। टी.पी.पी. से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए भारत के पास क्या विकल्प हैं?

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कुछ एशिया के देशों के मध्य मुक्त व्यापार सन्धियों है। इस समझौते के कई अवधान WTO के उपस्थानों से संगत नहीं हैं। WTO विशेष है व्यापार को सुगम बनाने पर जोर देता है जबकि TPP प्रभु, पर्यावरण, स्वास्थ्य मानकों के आधार पर अपने देशों में मूल देशों के उत्पादों के प्रवेश पर रोक लगाता है। इससे विकासशील देशों की वस्तुओं की निर्यात देशों के बाजारों तक पहुँच पर रोक लगने की संभावना है।

भारत पर प्रभाव

- भारत में प्रभु व पर्यावरणीय मानक लचीले होने के कारण भारत का इस क्षेत्र को होने वाला नुकसान कमरात्मक रूप से प्रभावित होगा।

- सेवाओं की शामिल करने के कारण भारत के सीपूवेयर उद्योग पर तत्कालीन प्रभाव। इससे भारत के माउट सीसिआ व सेवा निर्यात कम होने की संभावना है।
- भारत का दक्षिण पूर्व एशिया को होने वाला कामस्थितिकल निर्यात कम हो जाएगा।
- विपतगात जैसे देश भारत की हेमस-राइन इण्डस्ट्री को करीब कर देंगे।

इन सभी भाषाओं को से निपटने के लिए भारत इस के पास विकल्प -

- सबसे पहले तो भारत द्वारा अपने धरतु बाजार को निर्यात के विकल्प के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, इस कारण ~~निर्यात~~ व्यापार घात कम किया जा सकता है।
- भारत द्वारा सभी देशों के सापेक्षिकी संबंधों को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देना
- सारि, बिस्मलेन, क्रिस, डिमट लेस जैसे संगठनों को प्रकानी बनाना

• वैश्व अर्थव्यवस्था, अफ्रीका के इंफ्लेशन
मार्केट पर फोकस करना।

हैं एक विकल्प भारत के पास
चीन के "२ रीजनल काम्प्लीमेंट्री
इकोनॉमिक काम्प्लीमेंट्री एग्जिमेन्ट" से
जुड़ने का भी है। इससे भारत की
दीर्घकालिक रूप से फायदा छेगा। तथा
इस संगठन के अर्थ, पर्यावरण, स्वास्थ्य
संबंधी मानक भी भारत के समान ही
हैं। इससे भारत की एशिया, मैनेजिंग
के उभार को संतुलित करने में भी
सहायता मिलेगी।

11. Legal proceedings initiated by the Marshall Islands against India, Pakistan and Britain over nuclear weapons in the International Court of Justice highlights the issues of jurisdiction of the court. What is India's position vis-a-vis the jurisdiction of the ICJ? Also differentiate between binding and advisory pronouncements of the court with suitable examples.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) में मार्शल द्वीपसमूह द्वारा भारत, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के खिलाफ परमाणु हथियारों को ले कर आरम्भ की गयी कानूनी कार्यवाहियाँ वस्तुतः इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मुद्दे को उजागर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में भारत का क्या रुख है? साथ ही उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के बाध्यकारी तथा सलाहकारी निर्णयों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय UNO के छः अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय हैग में है। यह विश्व के देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है।

परंतु न्यायालय का क्षेत्राधिकार सभी राज्यों के 'बैरर क्षेत्राधिकार' से सीमित है। कोई भी राष्ट्र अपने किसी भी मुद्दे को यदि 'बैरर क्षेत्राधिकार' माने तो ICJ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

साथ ही सभी पक्षों की सहमति के बिना न्यायालय में कोई भी विवाद नहीं लाया जा सकता। केवल एक पक्ष की सहमति से विवाद का विस्तार संभव नहीं है।

इसके अलावा न्यायालय के निर्णयों को लागू करवाने का कोई माध्यम

नहीं है।

न्यायलय द्वारा कुछ निर्णय बाध्यकारी होते
हैं, जो दोनो पक्षों की सहज से
कोर्ट में जाए जाते हैं।

12. Even though the refugee crisis in Europe does not affect India directly, it presents an opportunity for India to showcase its commitment and capability to take greater responsibility in dealing with global issues. Comment in light of India's strengths, experience and international commitments regarding refugees.

यद्यपि, यूरोपीय शरणार्थी संकट का भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए वैश्विक मुद्दों से निपटने हेतु अधिक बड़ी ज़िम्मेदारी ग्रहण करने संबंधी प्रतिबद्धता तथा क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। शरणार्थी संबंधी भारत के सामर्थ्य, अनुभव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आलोक में इस पर टिप्पणी कीजिए।

विश्व में विद्यमान अशांति, विद्रोह, अदृष्टाव
के कारण शरणार्थी समस्या बनी हुई है।
शरणार्थी अन्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों
पर ही समस्या बनी हुई है। पाश्चिमी अफ्रीका
में बिसेकागर सीरिया के कारण यूरोप
में शरणार्थी की संख्या बढ़ रही है।

भारत शरणार्थी समस्या के समाधान
के लिए दबाव समूह के रूप में अपनी
भूमिका का निर्वहण कर सकता है।
क्योंकि UNO का सदस्य होने के कारण
भारत के पास विनासशील शक्तों की
आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है।

1951 के ~~विश्व~~ शरणार्थी
कन्वेंशन के अनुसार कोई भी राष्ट्र
शरणार्थियों को शरण देने से मना
नहीं कर सकता। भले भारत इस

इसका उभावी डिपान्वपन करवाया जाना
के लिए उपास करना चाहिए।

(१७) में बोम्बादेश के शरणार्थियों
पिटुई के समय श्रीलंका से भाग
शरणार्थियों से संबंधित समस्या के
समाधान का भारत के पास पर्याप्त
क्षमता भी है।

साथ ही पश्चिमी एशिया के
शांति स्थापित करने में भी भारत
सहयोग कर सकता है। जो कि भारत के
संबंध इन देशों के साथ अच्छे हैं। ताकि
वहाँ से शरणार्थियों की संख्या कम
की जा सके।

13. India is endowed with an amazing variety and wealth of soft power resources. Providing examples, illustrate the utilisation of soft power in diplomatic initiatives of the recent past. What are the limitations of the soft power approach in diplomacy in case of a developing country such as India?

भारत सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति) संसाधनों की आश्चर्यजनक विविधता एवं बहुलता से संपन्न है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, हाल के कूटनीतिक पहलों में सॉफ्ट पावर के उपयोग का वर्णन कीजिए। भारत जैसे किसी विकासशील देश के लिए कूटनीति में सॉफ्ट पावर एप्रोच (मृदु शक्ति उपागम) की क्या सीमाएं हैं?

~~भारत~~ सॉफ्ट पावर से गलत ढंग से, सांस्कृतिक तथा भय व दबाव के मध्य रास्ते के साथ प्रभावकारी संबंधों का निर्माण करना।

भारत के द्वारा सॉफ्ट पावर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक साधनों का सहारा लिया जाता है। भारत यूनि ऐलियेन्स रूप से पंचशील की विदेश नीति का पालन करता है, अतः भारत को सॉफ्ट पावर बनने से काफी लाभकारी मिले है।

• ट्रैक - डिप्लोमैसी के द्वारा भारत ने अन्य देशों विशेषकर पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए हैं।

• सड़की भरक के राजा को चैरमन जुमा मारफेद की उत्तिहति में दे करना

• चीन के प्रधानमंत्री के साथ शुल्कर

- बैठ कर अनौपचारिक बातें करना तथा
व्यक्तिगत तौरों से सहयोग
- अफगानिस्तान के अरंज-पेलारम,
सखेद, शकत, पुल-ए खुमरी का निर्माण,
इरान के चाबहार पोर्ट का निर्माण
सॉफ्ट पावर के उदाहरण हैं।
 - कोमलादेश की 1 बिलियन डॉलर का
बाइन ऑफ़ क्रेडिट, भूतान के पनबिजली
परियोजना का निर्माण, मालदीव के
कोरालीन प्लॉट के सुराव-छोटे परपानी
कॉम्प्लेक्स, अट्मीका में 50,000 दान वृक्षों
[0 बिलियन डॉलर का अनुदान केनकार
द्वारा भव्य देशों के साथ अंधुर संबंध
स्थापित करने का प्रयास है।
 - विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-
प्रदान, मेची खेलों का आयोजन आदि
उपरोक्त भारतीय सम्मेलन सॉफ्ट पावर
का ही परिणाम है।
- चूंकि भारत विश्व मुक्त रहा है
तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परम्परा
संयुक्त है अतः भारत के सॉफ्ट पावर
बनने की क्षमता है।

सीमाएँ :-

• भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान से सीमा संबंधी विवाद हैं। अतः यहाँ सॉफ्ट पावर के साथ ही हार्ड पावर की भी जरूरत है।

• भारत के बाहरी समस्या को निपटने के लिए वह प्रयोग अपेक्षित है।

• विकासशील देश होने के कारण सीमित आर्थिक संसाधन

• आंतरिक स्तर पर कई समस्याएँ हैं।

• वर्तमान परमाणु शक्तों के जुग में केवल सॉफ्ट पावर होने से काम नहीं चल सकता।

इस कारण भारत के लिए हथौड़ी के चीन के समान "नैरेट वास्तव" की नीति की आवश्यकता भी है।

14. Highlight the features of NAVIC and bring out its significance for India. How is it different from GAGAN? Examine whether NAVIC can be a replacement of GPS for India.

नाविक (NAVIC) की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा भारत के लिए इसके महत्व को उजागर कीजिए। यह गगन (GAGAN) से किस प्रकार भिन्न है? परीक्षण कीजिए कि क्या नाविक भारत के लिए जी.पी.एस. को प्रतिस्थापित कर सकता है।

नाविक भारत की उपग्रह आधारित मानचित्रण प्रणाली है। इसमें सात उपग्रह हैं। सिद्धि अब $7+2=9$ कर दिया जाएगा। इसमें निम्न सिंक्रोनास व स्टेशनरी दोनों प्रकार के उपग्रह हैं जो भारत की 24x7 365 सटीक जानकारी प्रदान करवाएँ। पूर्व में इसे IRNSS कहा जाता था।

महत्व :-

सैन्य :-

- यह भारत की 1500 किमी तक की सीमाओं की जानकारी प्रदान करेगा।
- प्रत्येक नौसैनिक को जानकारी
- सटीक चित्रण करने में सक्षम। इससे सीमा सुरक्षा में सहायता मिलेगी।
- अन्य देशों के साथ जानकारी साझा नहीं करनी पड़ेगी इससे ~~सैन्य~~ सुरक्षात्मक होने का खतरा नहीं रहेगा।
- सेना द्वारा आँकड़ों का उपयोग कर

रुकफिल्टरेशन को रोका जा सकेगा।

सिविल उपयोग:-

- ~~यही~~ भारत के जलमय क्षेत्रों की सटीक जानकारी इससे स्ट्रीट व्यू में मदद मिलेगी।
- आपदा प्रबंधन में मदद जैसे बाढ़, सुखा, सुनामी, भूकंप आदि में
- ट्रेकिंग प्रबंधन में मदद
- कैच डाइवरी द्वारा उपयोग।
- महिला सुरक्षा को बढ़ावा
- घर बैठे ही बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करना।

गगन से बिजला - गगन भारत की जीपीएस से जुड़ी दुर्ग सेवा प्रणाली है। इसने अमेरिका के उपग्रहों के माध्यम से भारत संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसे जीपीएस एडेड निपी ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। इस कारण भारत की रुफिना सूचनाओं में दृष्टिकोण की संभावना थी।

भारत में आत्मनिर्भरता आह्वान करने के लिए जीपीएस से प्राप्त सूचनाओं

के लिए दिए जाने वाले मापकल्प
 में भी कमी आ रही।
 परंतु नाविक जीपीएस की दिल्ली
 सटीक सूचनाएं देने में असमर्थ है क्योंकि
 जीपीएस में 30 उपग्रह हैं जबकि
 नाविक में केवल 3 हैं। जीपीएस
 6 मीटर तक की सटीक जानकारी दे
 सकता है जबकि नाविक 50 मीटर तक की
 परंतु यह भारत का
 स्वयं का एक रबी सिलसिला है तथा
 सुरक्षित भी है, मत! यह महत्वपूर्ण
 है।

15. What are Carbon Nanotubes (CNTs) and how are they an improvement over carbon fibres? Highlight the various unique properties of CNTs which makes them suitable to the manufacturing industry.

कार्बन नैनोट्यूब (सी.एन.टी.) क्या होते हैं तथा वे किस प्रकार कार्बन फाइबर से श्रेष्ठ हैं। सी.एन.टी. के उन विशिष्ट गुणधर्मों पर प्रकाश डालिए जो इसे विनिर्माण उद्योग हेतु उपयुक्त बनाते हैं।

नैनो ट्यूबों का उपयोग कर कार्बन के ट्यूब बनाए जाते हैं। ये खींचते बेलनाकार ट्यूब होते हैं जो कि गुणवत्ता में अच्छे व वजन में हल्के होने के कारण ज्यादा उपयोगी होते हैं।

कार्बन फाइबर ज्यादा तापमान सहन करने वाले, उच्च सुचालक, उच्च तन्यता, जल्दी ठुगने वाले, कम वजन वाले होते हैं। परंतु कार्बन नैनोट्यूब्स गुणवत्ता में कार्बन फाइबर से भी ज्यादा अच्छी होती हैं। इन सभी गुणों की भांति कार्बन नैनोट्यूब में ज्यादा पाई जाती है, इनकी सुचालकता ज्यादा तथा वजन कम होता है।

विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग :-

- विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत सरिपे, रोड आदि के निर्माण में इनका उपयोग किया जा सकता है।

- ज्यादा तापमान सहन कर सकने के कारण बिजिंग बनाने में उपयोग।
घरों के बाहरी हिस्से में छज्जे से छेद लगा रखने में मदद
- भूतचित्र हल्का होने से कम्य सेधी गमन बनाने में सहायता मिल सकती है।
- गुणवत्ता पुनर्निर्माण जा सकता है।
- भौतिकीकादर में ~~क~~ उपयोग किया जा सकता है।
- मैक इन इलेक्ट्रिक मिशन में वास्तु प्राप्त होता।

16. Explain the significance of gravitational waves recently detected by LIGO. What are the objectives of the recently envisaged LIGO-India project and what benefits will India accrue from it?

हाल ही में एल.आई.जी.ओ. (लिगो) द्वारा खोजे गए गुरुत्वीय तरंगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। हाल ही में परिकल्पित एल.आई.जी.ओ.-इंडिया प्रोजेक्ट (लिगो-भारत परियोजना) के क्या उद्देश्य हैं, तथा भारत को इससे क्या लाभ होंगे?

गुरुत्वीय तरंगों जो
निश्चित स्पेस एवं टाइम में फैला होने
वाली किरणें हैं जो किसी माध्यम से
गुजरने पर अपरिवर्तित रहती हैं। ये कुछ
~~गुरुत्वीय तरंगों के समान हैं~~ निश्चित ब्रह्मानों
से ही उत्पन्न होती हैं।

महत्व —

- गुरुत्वीय तरंगों से ब्रह्माण्ड को समझने में मदद मिलेगी।
- इससे संपूर्ण विश्व की ही एक उपयोगिता के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। क्योंकि उपयोगिता है गुरुत्वीय तरंगों की उत्पन्न करना काठिन है।
- ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार भादि क्षेत्रों में मदद मिलेगी।
- थर्मोडायनामिक्स, फॉटोनिक्स, न्यूक्लियर विज्ञान भादि के क्षेत्र में नये विचार संभव हैं।
- सिस्मिक वेव्स के क्षेत्र में नये प्रयोग व जानकारी संभव है।

- वृद्धावस्था की वृत्तियों के रहस्यों से पर्दा उठेगा।
- ऐसे मॉडल जो 'लाइव एजेंडा' नहीं करते उन्हें समझने में मदद मिलेगी।
- भाविष्य में यदि गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर का आविष्कार कर लिया जाए तो संचार, चिकित्सा भादि क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है।

लिंगी भारत परियोजना -

गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए लेंजर इंटरफेरोमीटर रेजिशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में उपयुक्त दो डिटेक्टरों की पहचान भारत ने तैयार की है। भारत का उद्देश्य इस परियोजना से होने वाले लाभों में भागीदार बनना है।

इससे भारत की विश्व स्तर पर पहचान मिली है। तथा भारत ने रिसर्च को बढ़ावा मिला है। भारत के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा व प्रोत्साहन मिला है।

17. What are the criteria employed for a pandemic to be declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the WHO? In the wake of recent Ebola and Zika virus outbreaks examine the efficacy of the prevalent architecture of global health governance. Also, assess India's preparedness in handling such global epidemics.

डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा किसी महामारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न (PHEIC) के रूप में घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं? हाल ही में इबोला तथा जीका विषाणु के प्रसार के सन्दर्भ में वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता की जाँच कीजिए। ऐसी वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन कीजिए।

WHO इस किसी भी बीमारी को PHEIC घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं:-

- बीमारी व्यापक रूप से लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हो।
- अचानक से उत्पन्न, जिसमें प्रभावी इलाज की व्यवस्था नहीं।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना हो।

हाल ही में इबोला व जीका वायरस के संबंध में WHO ने ऐसा ही किया। क्योंकि दोनों ही बीमारियों ने एशिया, अफ्रीका के साथ ही अमेरिका व लैटिन अमेरिका को प्रभावित किया।

जीका वायरस से प्रभावित व्यक्ति के लिए अभी तक कोई ठीक ठीक निश्चित नहीं किया गया तथा इबोला बीमारी काफी समय बाद निरसित किया गया।

~~इससे~~ परंतु WHO दोनों बीमारियों की
रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए
इसीलिए उभाविर देशों के यात्रियों के
दूसरे देशों में यात्रा पर प्रतिबंध
लगाया। दवाइयों का वितरण सुनिश्चित
करवाया। WHO की टीम ने स्वयं उभाविर
देशों में जाकर दवा वितरण किया।

भारत की तैयारी:-

भारत में इन बीमारियों के बारे में
जागरूकता फैलाई गई है। निम्नलिखित माध्यमों
से जैसे - सोशल मीडिया।

- स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सफाई अभियान
- भण्डारों को मारने के लिए दवा नष्ट कर
भाँटि
- एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले
यात्रियों की गहन जाँच ताकि संक्रमित
मांस को नहीं खेता जा सके।

मध्यम भारत ने इसके लिए तैयारी की है।
परंतु भारत की बहुत सी जनसंख्या
गिरिधर व गरीब है अतः उसे घरी

तरह जागरूक नहीं किया गया है।
 WTO व विभिन्न देशों ने भारत के
 कम्पवसरी लाइसेंसिंग व जेनरल इगस काफ़ी
 विरोध किया है। इससे पर्याप्त इगस
 निर्माण में बाधित है।
 खा क्षेत्र में पर्याप्त R & D
 का अभाव है।

18. Give a brief explanation of CRISPR - gene editing technology. Also discuss its significance in modern biology and agriculture.

जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी - सी.आर.आई.एस.पी.आर. (CRISPR) की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। आधुनिक जीव-विज्ञान तथा कृषि में इसके महत्व पर भी चर्चा कीजिए।

बायो टैम्पोरलॉजी का प्रयोग करते हुए किसी जीन को हटाना, बदलना या नया जीन जोड़ना जीन एडिटिंग कहलाता है। क्रिस्पर जीन एडिटिंग की ही एक तकनीक है। जिसमें क्रिस्पर एक आणविक कुंजी के समान कार्य करते हुए जीन में परिवर्तन करता है। क्रिस्पर सर्वप्रथम प्रभावित जीन को छेद करता है तथा उसके पश्चात् उस जीन को काटकर दोनों सिरों से जोड़ देता है।

उसके पश्चात् पुनर्संयोजित जीन अपने भाप को पूर्व जीन सीक्वेंस के समान विकसित कर लेता है। यह जीन एडिटिंग की एक आणविक, सटीक व अधिक सस्ती तकनीक है।

महत्व — जीव विज्ञान में

- जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जा सकता है।

- मल्टीड्रमर, पर्मिशन जैसी बीमारियों का स्थापन संभव
- कैंसर से प्रभावित कीडिकाओं को हानि में मदद
- भानुवाशिक रोगों का स्थापन संभव है।
- जन्मजात विकारों को दूर करने में सहायक

कृषि में महत्व :-

- GM फसलों में उपभोग
- सूखा रोधी व बाढ़ में उगने वाली फसलों उगाना संभव
- फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
- बीजों में इस प्रकार परिवर्तन की खरपतवार व कीटकाओं के कण उपभोग की आवश्यकता
- अधिक उत्पादकता भाकि ।

19. Even though large infrastructure projects like High Speed Rail (HSR) facilitate greater technological development, they come with their own set of challenges. Examine in the context of proposed HSR projects in India. Suggest some measures on how HSR can truly be 'Made in India'.

यद्यपि हाई स्पीड रेल (एच.एस.आर.) जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकीय विकास में सहायता करती हैं, लेकिन उनकी भी अपनी चुनौतियां होती हैं। भारत में प्रस्तावित एच.एस.आर. परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में परिक्षण कीजिए। कुछ उपाए बताइये कि कैसे सही मायने में एच.एस.आर. 'मेड इन इंडिया' हो सकता है।

हाई स्पीड रेल्वे की निम्नलिखित चुनौतियां हैं: —

- भारत में इस तरह की परियोजनाओं के लिए तकनीक नहीं है। बाहर से तकनीक का आयात करने पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है।
- विविध समस्याएं। यह तकनीक मलेशिया खरीदी है, राजकीय बाग बंदी है।
- नई पटरियां खिलाने में मलेशिया खर्च।
- रेल याता माहलगी होने के कारण लागत वसूली की समस्या।
- भौगोलिक समस्याएं।
- राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव

PSD

HSR को गैर इन इच्छा बनाने के लिए
निम्नलिखित उपास करने होंगे। -

- तकनीक का आयात करने की
आपत्तिका देना तथा निर्यात
वस्तुओं के।
- R & D को बढ़ावा देना।
- "गैर इन इच्छा" स्टार्ट-अप इच्छा
आदि का उभावी रियान्सन
- तकनीकी विकास का उपास करना
- रेल के डिब्बे, कल-पुर्जे आदि का
निर्माण भारत में किया जाना।

20. What do you understand by Big-data? Using SDGs as an example, discuss its role in effective implementation of public policy. Also mention challenges faced in using Big-Data and measures to overcome them.

बिग-डेटा से आप क्या समझते हैं? एस.डी.जी. को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए सार्वजनिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त, बिग-डेटा के प्रयोग में आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान के उपायों पर भी चर्चा कीजिए।

बिग-डेटा सूचनाओं का डैटा की व्यापक मात्रा है। इसका विश्लेषण कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। इससे नए नए माध्यम से ताकि इससे कुछ पैटर्न, ट्रेण्ड, आदि के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। ये निष्कर्ष नतीजे के आधार पर विचारकलापों से संबंधित हो सकते हैं।

सर्व विषय लक्ष्यों में 17 लक्ष्य रखे गए हैं। ये लक्ष्य 169 भागों में बँटे हुए हैं। इनमें भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, अवसरों के बँटव पर्यावरण व निष्ठाओं तक की शामिल किया गया है। इन सभी से संबंधित जानकारी, सूचनाओं, कार्यक्रमों के

घारे में निष्कर्ष बिग-डेरा के
भाधार पर निर्धार जा सकते हैं।
विभिन्न देशों, व्यक्तियों के व्यवहार व
भावनाओं के लिए प्रत्येक प्रकार की हैं।
इस कारण इन लोगों को धारा
करने का प्रयास उसी रूप में किया
जा सकता है।

गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी
पुनर्विचारों से निपटने के लिए बिग-डेरा
का प्रयोग कर विशेषीकृत उपकरणों
जा सकते हैं।

पुनर्विचारों व समाधान

- बिग-डेरा के रख रखाव की समस्या।
- विश्लेषण करने में समस्या।
- पुराने सॉफ्टवेयर के उपयोग से
बिग-डेरा विश्लेषण संभव नहीं।
- मानव व्यवहार व प्रतिक्रियाओं में
परिवर्तन।

क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग से
सिग-उंटा की समस्या को दूर करने
का प्रयास किया जा रहा है। सुपर
कंप्यूटर के उपयोग से भी सिग-उंटा
की चुनौतियों को दूर किया जा सक
ता है।